

न्यूज टुडे

RBI और बैंक मिलकर 'डिजिटल पेमेंट इंटेलेजेंस प्लेटफॉर्म' (DPIP) विकसित करेंगे

DPIP को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की निगरानी और मार्गदर्शन में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) के रूप में विकसित किया जाएगा।

► DPI का तात्पर्य उन आधारभूत डिजिटल प्रणालियों से है, जो सभी के लिए सुलभ, सुरक्षित और अंतर्संचालनीय हैं। ये जरूरी सार्वजनिक सेवाओं का आधार बनती हैं। उदाहरण के लिए: आधार, यूनिकाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) आदि।

डिजिटल पेमेंट इंटेलेजेंस प्लेटफॉर्म (DPIP) के बारे में

► इसका उद्देश्य उन्नत तकनीकों का उपयोग करके वास्तविक इंटेलेजेंस साझा करके और उसे समेकित करके धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन को मजबूत करना है।

► यह बैंकों के बीच समन्वय को बढ़ाकर मौजूदा धोखाधड़ी पहचान प्रणाली को भी मजबूत करेगा।

► श्री ए.पी. होता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो DPIP की स्थापना से जुड़े विविध पहलुओं की जांच करेगी।

► रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (RBIH) को 5 से 10 बैंकों की सलाह से DPIP का एक प्रोटोटाइप (मॉडल) तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है।

⊕ इसमें निजी और सरकारी दोनों प्रकार के बैंकों से सलाह ली जाएगी।

► DPIP की आवश्यकता क्यों है?

⊕ RBI की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, बैंकिंग सेक्टर में धोखाधड़ी के मामलों में काफी वृद्धि हुई है।

⊕ वित्त वर्ष 2024-25 में 36,014 करोड़ रुपये मूल्य के धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए थे, जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 12,230 करोड़ रुपये था।

बैंक धोखाधड़ी को रोकने के लिए RBI द्वारा शुरू की गई अन्य पहलें

► मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन: सभी बैंकों हेतु इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होने वाले सभी भुगतानों के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू करना अनिवार्य किया गया है।

► ग्राहकों की कोई जिम्मेदारी नहीं (Zero Liability): यदि नुकसान बैंक की लापरवाही या थर्ड पार्टी की गलती से होता है, तो ग्राहक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

► bank.in और fin.in डोमेन: ग्राहकों को असली और नकली बैंकिंग वेबसाइट्स में अंतर समझने में मदद करने के लिए ये डोमेन बनाए गए हैं।

वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (FATF) ने "जटिल प्रसार-वित्तपोषण और प्रतिबंधों से बचाव योजना" पर रिपोर्ट जारी की

यह रिपोर्ट वैश्विक वित्तीय प्रणाली में "प्रसार-वित्तपोषण (Proliferation Financing)" को रोकने में निहित गंभीर कमियों को उजागर करती है।

► प्रसार वित्तपोषण से आशय है सामूहिक विनाश के हथियारों (Weapons of Mass Destruction)" के निर्माण हेतु व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए फंड, अन्य संपत्तियां या संसाधन जुटाना, स्थानांतरित करना या उपलब्ध कराना। यह वैश्विक सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली के समक्ष गंभीर खतरा है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

► विश्व के लिए खतरा: वर्तमान में खतरा यह है कि राज्य और गैर-राज्य अभिकर्ता (नॉन-स्टेट एक्टर्स) दोहरे-उपयोग (dual-use) वाले सामान, तकनीक एवं ज्ञान प्राप्त करने के लिए खरीद-नेटवर्क (procurement networks) का उपयोग कर रहे हैं।

► वैश्विक व्यवस्था की कमियां: केवल 16% देश सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार को रोकने वाले 'संयुक्त राष्ट्र' के लक्षित प्रतिबंधों को प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं।

► गैर-कानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकें:

⊕ प्रतिबंधों से बचने के लिए मध्यवर्तियों का उपयोग: खरीद-नेटवर्क के वास्तविक खरीदार अपनी पहचान छिपाने के लिए फ्रंट या शेल कंपनियों, वित्तीय बिचौलियों, और तीसरे देश के मार्गों का उपयोग करते हैं।

⊕ स्वामित्व छिपाना: विशेष रूप से डिजिटल माध्यम से सामानों या तकनीकों के मूल खरीदार के सामने नहीं आने की वजह से उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

⊕ वर्चुअल एसेट्स का उपयोग: प्रतिबंधित व्यक्ति या संगठन वर्चुअल करेंसी और नई तकनीकों का उपयोग कर सीधे या प्रतिबंधों का अनुपालन नहीं करने वाले देशों के माध्यम से फंड ट्रांसफर करते हैं।

⊕ समुद्री मार्ग का दुरुपयोग: "डार्क फ्लीट" जैसे जटिल शिपिंग नेटवर्क का उपयोग करके जहाजों की पहचान छिपाई जाती है और प्रतिबंधों से बचा जाता है।

♦ उदाहरण के लिए- भारतीय जांचकर्ताओं ने पाकिस्तान जा रहे एक जहाज पर दोहरे-उपयोग वाले उपकरण होने की पुष्टि की थी, जबकि पहले इन उपकरणों के बारे में नहीं बताया गया था।



FATF की रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशें

► प्रसार-वित्तपोषण के लिए अपनाए जा रहे नए तरीकों से निपटने हेतु खतरों का नियमित रूप से आकलन और अपडेट करते रहना चाहिए।

► प्रसार-वित्तपोषण और प्रतिबंधों से बचने के प्रयासों का पता लगाने हेतु सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की क्षमता को मजबूत करने में सूचना साझा व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहिए।

► अगले 5 वर्षों में FATF की शब्दावली में सामूहिक विनाश के हथियार के प्रसार-वित्तपोषण की स्पष्ट परिभाषा जोड़ी जानी चाहिए। इससे विश्व के देशों के बीच समन्वय बढ़ेगा।

► अगले 3 वर्षों में वैश्विक प्रसार-वित्तपोषण के खतरों के आकलन की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि सर्वोत्तम कार्य-पद्धतियों को पहचाना जा सके और कार्रवाईयों को मजबूत किया जा सके।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 'ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2025' रिपोर्ट जारी की

यह वैश्विक तंबाकू एपिडेमिक पर WHO की 10वीं रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट 2008 से देशों द्वारा तंबाकू नियंत्रण में की गई प्रगति का आकलन करती है।

- WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (WHO-FCTC) देशों को इसके तंबाकू नियंत्रण प्रावधानों को अपनाकर और उन्हें लागू करके तंबाकू से होने वाले नुकसान को कम करने में मदद करता है।
 - WHO-FCTC के प्रावधान केवल तंबाकू की मांग पर ही नियंत्रण नहीं लगाते, बल्कि उसके उत्पादन, वितरण, उपलब्धता और आपूर्ति को भी नियंत्रित करते हैं।
- WHO ने 2008 में MPOWER रणनीति शुरू की थी। इसका उद्देश्य देशों को FCTC प्रावधानों को जमीनी स्तर पर लागू करने में मदद करना है।
 - MPOWER की 6 प्रभावी नीतियां तंबाकू सेवन को कम करने पर केंद्रित हैं (इन्फोग्राफिक्स देखें)।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- वर्ष 2007 के बाद से 155 देशों ने MPOWER की कम-से-कम एक नीति लागू की है, जिससे 6.1 बिलियन लोगों को लाभ हुआ है।
- सभी MPOWER उपायों में से सबसे अधिक प्रगति सिगरेट के पैकेट्स पर बड़े ग्राफिक स्वास्थ्य चेतावनियों में देखी गई है।
- भारत ने तंबाकू के विज्ञापन, प्रचार और प्रायोजन (TAPS) पर सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर सख्त रोक लगाई है।
- तंबाकू पर टैक्स लगाना MPOWER की सबसे कम अपनाई गई नीति है। भारत में सिगरेट अब भी सस्ती है।
- भारत दुनिया का पहला देश बना है, जिसने डिजिटल स्ट्रीमिंग कंटेंट पर भी तंबाकू नियंत्रण नियम लागू किए हैं।

MPOWER नियंत्रण उपाय



तंबाकू के उपयोग और रोकथाम की नीतियों की निगरानी करना



धूम्रपान-मुक्त वायु कानून के माध्यम से लोगों को तंबाकू के धुएँ से बचाना



तंबाकू छोड़ने में मदद की पेशकश करना



पैकेज लेबल और जनसंचार माध्यमों से तंबाकू के खतरों के बारे में चेतावनी देना



तंबाकू विज्ञापन, प्रचार और प्रायोजन पर प्रतिबंधों को लागू करना



तंबाकू पर टैक्स बढ़ाना

रसायन, अपशिष्ट और प्रदूषण पर अंतर-सरकारी साइंस-पॉलिसी पैनल की स्थापना की गई

इसकी स्थापना का निर्णय 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा (UNEA) द्वारा पारित एक प्रस्ताव के बाद लिया गया था। इस प्रस्ताव में इस प्रकार की एक अंतर-सरकारी संस्था स्थापित करने की मांग की गई थी।

- इस पैनल से जुड़ी वार्ताओं का आयोजन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा किया गया था, जो अब इस पैनल का मुख्यालय भी होगा।
- नया पैनल राष्ट्रों को रसायनों, अपशिष्ट और प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित मुद्दों पर स्वतंत्र व नीति-प्रासंगिक वैज्ञानिक सलाह भी प्रदान करेगा।

- अगला कदम इस पैनल के पहले पूर्ण सत्र (plenary session) की तैयारी करना है। इस सत्र में सरकारें इसके प्रारंभिक कार्य हेतु कार्यक्रम, प्राथमिकताओं और साझेदारी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगी तथा उन्हें अपनाएंगी।

- यह पैनल जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) और जैव विविधता एवं पारिस्थितिकी-तंत्र सेवाओं पर विज्ञान-नीति मंच (IPBES) के साथ विश्व का तीसरा वैज्ञानिक सलाहकारी मंच है।

पैनल की आवश्यकता क्यों है?

- त्रिप्लैनेटरी संकट (Triple Planetary Crisis) के प्रभाव को कम करने के लिए: इसमें जलवायु परिवर्तन; प्रकृति और जैव विविधता की हानि तथा प्रदूषण व अपशिष्ट का संकट शामिल है।
- रसायनों, अपशिष्ट और प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए:
 - आज की आधुनिक जीवनशैली में उपयोग होने वाले रसायनों की मात्रा बढ़ गई है, जिनसे अनचाहे और नुकसानदायक प्रभाव पैदा हो रहे हैं।
 - घरों और शहरों से निकलने वाला ठोस अपशिष्ट 2023 में लगभग 2.1 बिलियन टन था, जिसके 2050 तक बढ़कर करीब 3.8 बिलियन टन होने की संभावना है।
 - पिछले दो दशकों में नए तरह के प्रदूषण करीब 66% बढ़ गए हैं।



विश्व में जारी संघर्ष से पर्यावरण पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है

वर्तमान में विश्व में जारी भू-राजनीतिक संघर्षों से पर्यावरण पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। इन प्रभावों में ईरान के परमाणु ठिकानों से रेडियोएक्टिव संदूषण फैलना भी शामिल है।

संघर्षों/ युद्धों का पर्यावरण पर प्रभाव

- ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन: वैश्विक सैन्य गतिविधियां 5.5% वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं।
- प्रदूषण और संदूषण: पूर्वी यूक्रेन के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पावर प्लांट्स, केमिकल फैक्ट्री, तथा पुरानी खदानों से अधिक हानिकारक विषाक्त प्रदूषक उत्सर्जित होने का खतरा बढ़ गया है।
 - ⊕ यूक्रेन में लैंडमाइंस और निष्क्रिय विस्फोटक भविष्य में घातक साबित हो सकते हैं। इसके अलावा, सैन्य गतिविधियों की वजह से मृदा, जल और जंगल प्रदूषित हो रहे हैं। इनकी सफाई की अनुमानित लागत लगभग 34.6 अरब अमेरिकी डॉलर है।
- घटते संसाधन और जैव विविधता को नुकसान: युद्ध और संघर्ष वनों की कटाई को बढ़ावा देते हैं तथा कृषि कार्य को बाधित करते हैं। यही नहीं, सैन्य गतिविधियों से वन्यजीवों के पर्यावास नष्ट होते हैं और अवैध शिकार को बढ़ावा मिलता है। इससे जैव विविधता को नुकसान पहुंचता है।
 - ⊕ उदाहरण के लिए- वियतनाम युद्ध के दौरान, एजेंट ऑरेंज जैसी शाकनाशियों (हर्बिसाइड) के व्यापक उपयोग के चलते विशाल वन क्षेत्र नष्ट हो गया था।

अंतर्राष्ट्रीय समझौते

- पेरिस समझौता 2015: इसमें सैन्य गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की स्वैच्छिक रिपोर्टिंग का प्रावधान किया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की रोम संविधि (Rome Statute), 1998: इसमें अंतर्राष्ट्रीय सशस्त्र संघर्षों के दौरान पर्यावरण को व्यापक, दीर्घकालिक और गंभीर क्षति को 'युद्ध अपराध' माना गया है।
- पर्यावरण संशोधन तकनीकों के सैन्य या किसी अन्य शत्रुतापूर्ण उपयोग पर प्रतिबंध पर कन्वेंशन (ENMOD): यह कन्वेंशन पर्यावरण में संशोधन करने वाली तकनीकों (जैसे मौसम में कृत्रिम बदलाव) के सैन्य या शत्रुतापूर्ण उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।



अन्य सुर्खियां



इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC)

भारत ने इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) की बैठक में भारत से संबंधित संदर्भों को अनुचित और तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए खारिज कर दिया।

इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के बारे में

- स्थापना: इसकी स्थापना 1969 में रबात (मोरक्को) में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में हुई थी।
- मुख्यालय: जेद्दा (सऊदी अरब)।
- सदस्य: यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है। इसके 57 सदस्य हैं और ये सदस्य चार महाद्वीपों के हैं।
- भूमिका: यह मुस्लिम जगत का सामूहिक प्रतिनिधित्व करता है।



थर्स्टवेव

शोधकर्ताओं ने एटमोस्फियरिक थर्स्ट की दीर्घावधि का वर्णन करने के लिए एक नया शब्द "थर्स्टवेव्स" गढ़ा है। थर्स्टवेव क्या है?

- थर्स्टवेव वह स्थिति होती है जब कम-से-कम लगातार तीन दिनों तक वाष्पीकरण की मांग उस अवधि के लिए अपने 90वें प्रतिशत मान से अधिक हो जाती है।
 - ⊕ वाष्पीकरणीय मांग इस बात की माप है कि वायुमंडल में जलवाष्प ग्रहण करने की कितनी क्षमता मौजूद है।
- तापमान, पवन की गति, आर्द्रता और धूप सहित कई कारकों का संयोजन वाष्पीकरणीय मांग को बढ़ाता है।
- इन 'थर्स्टवेव्स' का अध्ययन किसानों को अपने जल संसाधनों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और फसल की पैदावार में सुधार करने में मदद कर सकता है।



‘एशिया में जलवायु की स्थिति 2024’ रिपोर्ट

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) ने ‘एशिया में जलवायु की स्थिति 2024’ रिपोर्ट (State of the Climate in Asia 2024 Report) जारी की है।

- ▶ विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
- ▶ रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर
- ▶ सबसे गर्म वर्ष: साल 2024 एशिया का अब तक का सबसे गर्म या दुनिया का दूसरा सबसे गर्म वर्ष रहा, जिसमें तापमान 1991-2020 के औसत से 1.04°C अधिक दर्ज किया गया।
- ▶ तापवृद्धि की दर अधिक होना: एशिया की तापवृद्धि दर वैश्विक औसत से दोगुनी है।
- ▶ ग्लेशियर का पिघलना: कम बर्फबारी और अत्यधिक गर्मी के कारण मध्य हिमालय और तियान शान में ग्लेशियर पिघल रहे हैं।
- ▶ रिकॉर्ड समुद्री तापमान: समुद्री सतही जल में अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया।
- ▶ समुद्री जल के तापमान में दशकीय वृद्धि दर वैश्विक औसत ताप-वृद्धि दर से लगभग दोगुनी है।



ब्लोआउट

असम में एक तेल कुएं में ब्लोआउट के कारण हुए प्राकृतिक गैस रिसाव को नियंत्रित करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ONGC) ने वैश्विक विशेषज्ञों की मदद ली है।

ब्लोआउट क्या है?

- ▶ ब्लोआउट तेल/गैस कुएं में होने वाली एक दुर्घटना है जहाँ भूमिगत दबाव के कारण गैस या तेल अनियंत्रित रूप से सतह पर आ जाता है।
- ▶ बाहर निकलने के दौरान, गैस ड्रिलिंग लिफ्टिड, रेत और कभी-कभी तेल के साथ मिल जाती है और अनियंत्रित जेट के रूप में सतह पर निकलती है।
- ▶ कारण: यह घटना वाल्व के फेल होने या दबाव का गलत आकलन करने के कारण घटित होती है, जिससे ज्वलनशील पदार्थों का अचानक उत्सर्जन हो जाता है।
- ▶ दुष्प्रभाव: ब्लोआउट के गंभीर दुष्प्रभावों में शामिल हैं: भीषण आगजनी, विस्फोट, वायु-प्रदूषण और जनहानि, आदि।



ULLAS (नव भारत साक्षरता कार्यक्रम)

लिपुला ULLAS/ उल्लास कार्यक्रम के तहत मिजोरम और गोवा के बाद तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है।

- ▶ किसी राज्य को पूर्ण साक्षर बनने के लिए, उसे 15 वर्ष और उससे अधिक की आयु के व्यक्तियों में कम-से-कम 95% साक्षरता दर प्राप्त करनी होती है।
- ▶ ULLAS (नव भारत साक्षरता कार्यक्रम/ न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम) के बारे में
- ▶ संबंधित मंत्रालय: शिक्षा मंत्रालय।
- ▶ योजना का प्रकार: केंद्र प्रायोजित योजना।
- ▶ कार्यक्रम की अवधि: वित्तीय वर्ष 2022-2027
- ▶ उद्देश्य: देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के निरक्षरों को साक्षर बनाना।
- ▶ लक्ष्य: 5 करोड़ लोगों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान उपलब्ध करवाना।
- ▶ कार्यान्वयन: यह योजना ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों (हाइब्रिड मोड) में चलाई जा रही है।



रिसाइकल प्लास्टिक

एक नए अध्ययन में रिसाइकल प्लास्टिक से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले गंभीर दुष्प्रभावों पर गंभीर चिंता जताई गई है।

अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- ▶ एकल रिसाइकल प्लास्टिक पेलेट में 80 से अधिक प्रकार के रसायन पाए गए हैं।
- ▶ ये रसायन रिसकर जलापूर्ति प्रणाली में मिल सकते हैं और हमारी हार्मोन-प्रणाली और मेटाबॉलिज्म (चयापचय) के कार्य को बाधित कर सकते हैं।

रिसाइकल प्लास्टिक के बारे में

- ▶ इसमें उपयोग की गई प्लास्टिक सामग्री को इकट्ठा कर, यांत्रिक या रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से तोड़ा जाता है और फिर उसे कच्चे माल में बदल दिया जाता है। इसका उपयोग नए प्लास्टिक उत्पादों के निर्माण में किया जाता है।
- ▶ यह प्रक्रिया नए प्लास्टिक के उत्पादन की आवश्यकता को कम करती है, ऊर्जा की बचत करती है और प्रदूषण को कम करने में सहायक होती है।



पहली राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहेमेटोलॉजी (NIIH) ने भारत की पहली राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री स्थापित की है।

- ▶ NIIH संस्था, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के तहत कार्य करती है।
- ▶ ‘राष्ट्रीय दुर्लभ रक्तदाता रजिस्ट्री’ के बारे में
- ▶ उद्देश्य: ऐसे रोगियों की मदद करना जिनके रक्त-समूह दुर्लभ हैं और जिन्हें बार-बार रक्त चढ़ाने की आवश्यकता होती है।
- ▶ दुर्लभ रक्त दाताओं की परिभाषा:
 - ▶ आमतौर पर, दुर्लभ रक्त दाता ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिसमें वह एंटीजन अनुपस्थित होता है जो अधिकतर आबादी में प्राप्त होता है और ऐसे लोगों की औसत संख्या 1,000 में 1 या इससे कम होती है। ऐसे व्यक्ति को भी दुर्लभ रक्त दाता कहा जाता है जिनमें कई कॉमन एंटीजन प्राप्त नहीं होते हैं, जो किसी दाता में एक साथ शायद ही कभी पाए जाते हैं।
 - ▶ अधिकतर आबादी में प्राप्त लेकिन किसी व्यक्ति में अनुपस्थित एंटीजन वाले दुर्लभ रक्त समूह के उदाहरण: Rhnull, बॉम्बे (Oh), Jr(a-) आदि।



अंबुबाची मेला

असम के कामाख्या मंदिर में हर साल लगने वाले अंबुबाची मेले के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे हैं।

अंबुबाची मेला के बारे में

- ▶ यह असम के कामाख्या मंदिर में मानसून के दौरान आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू मेला है।
- ▶ कामाख्या मंदिर गुवाहाटी के पास नीलांचल पहाड़ियों पर स्थित है।
- ▶ यह मंदिर तांत्रिक पूजा के प्रमुख केंद्रों में से एक है और सबसे बड़े शक्तिपीठों में से एक है।
- ▶ यह मेला प्रजनन क्षमता, मानसून के आगमन और संस्कृतियों में पृथ्वी को एक उर्वर स्त्री के रूप में पारंपरिक विश्वास का प्रतीक है।

सुर्खियों में रहे स्थल



कतर (राजधानी: दोहा)

ईरान ने कतर स्थित पश्चिम एशिया के सबसे बड़े अमेरिकी सैन्य अड्डे, अल-उदैद एयर बेस पर मिसाइल हमला किया है।

भौगोलिक अवस्थिति:

- ▶ अवस्थिति: कतर एक प्रायद्वीप है, जो अरब की खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित है।
- ▶ स्थलीय सीमा: इसकी एकमात्र स्थलीय सीमा सऊदी अरब के साथ लगती है।
- ▶ समुद्री सीमाएं: ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ लगती है।

भौगोलिक विशेषताएं:

- ▶ इस देश में स्थलाकृतिक विविधता बहुत कम है। इसका अधिकांश भू-भाग समतल है। इसके उत्तर में छोटे-छोटे कार्बोनेट पर्वत (दुखन क्षेत्र) और दक्षिण-पूर्व में रेतीले टीले यथा- उम्सईद, खोर-अलुदैद हैं।
- ▶ नदियां: कतर में कोई नदी या झील नहीं है। यहां जल का प्राथमिक स्रोत वर्षा और भू-जल है।



अहमदाबाद



बेंगलूर



भोपाल



चंडीगढ़



दिल्ली



गुवाहाटी



हैदराबाद



जयपुर



जोधपुर



लखनऊ



प्रयागराज



पुणे



राँची